449 Rule 377

Rule 377

450

that for systematic and expenditious development of the coal resources of Orissa and to ensure co-ordination and efficiency, the two coal producing areas in the State should be brought under the administrative control of separate subsidiary company of Coal India Ltd with headquarters in Orissa.

MR. CHAIRMAN: Shri Shri Desai. Absent. Satyanarayan Jatiya.

(vi) Need to provide immediate medical assistance to people of Ghumanpura Village, Bhind, where children are dying of a mystery disease.

भी सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय. मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान करना चाहता हं-

देश में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा स्विधा के बिस्तार की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव में जनजीवन असूरक्षित है। गांवों में उपचार के अभाव में अकाल मौत की बेबसी है। सर-कारी स्वास्थ्य संस्थायें और सेवायें गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं हैं तथा विकास खंड मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। सामान्य औषधियां और जांच सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वधी एक सी" पर उपलब्ध नहीं है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा रक्षक 'बिना दवाओं केन तो ग्रामीण की स्वास्थ्य सेवा करने में और न ही स्वास्थ्य रक्षा करने में समर्थ हैं। विगत दिनों मध्य-प्रदेश के मुरेना जिले के मसावनी गांव के 23 बच्चों की मौत के हादसे के बाद भिण्ड जिले के गुमानपूरा गांव में रहस्यमय बीमारी

के कारण 24 मासुस हिरिजन बच्चों को

मौत का विकार होना पड़ा है तथा उनके

बच्चे अभी भी इस बीमारी से प्रसित हैं। प्राय: प्रतिदिन किसी न किसी बच्चे की मृत्यू के कारण गांव के लोग असहाय और गहन निराशा की स्थिति में हैं। अतएव यह आवश्यक है कि उक्त गांव के लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गाँवों में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा उप-लब्ध कराने हेत् चिकित्सा संस्थाओं को सक्षम बनाने तथा गांव तथा चिकित्सा हेत् "मोबाइल स्वास्थ्य सेवाए" प्रारम्भ की जाए।

(vii) Need to implement the Sethusamudram Canal Project.

SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirapalli): The recent expert Committee assessed that the net rate of return may vary between 4.72 and 11.93 per cent under different sets of assumptions and hence it will not be economically viable. I request that the above Sethusamudram Canal Project shou'd be taken up for the following reasons:

- (i) The Canal will provide an unbroken navigable route around the peninsula, with a saving in distance of 300 to 400 mautical miles for steamers going from the East Coast to the West Coast.
- (ii) This will result in a reduction in fuel cost and a lessening of voyage time which can help save Rs. 80,000 per voyage.
- (iii) It will also stimulate industrial development in the hinterland and establish a new facility for the speedy movement of traffic.
- (iv) With the expansion of the Tuticorin complex, Thermal

[Shri N. Selvaraju]

Power Station and Refinery, additional movement of traffic and custom is fast building up.

- (v) The Indian Navy will have the advantage of moving from Palk Straits into the Gulf of Manner without having to cruise through international waters.
 - (vi) There are ample possibilities to develop the hinterland which will increase the potential economic benefits.

I, therefore, request the Government of India to come forward to take up the project for implementation n the best interest of the nation without any more delay as it will push up the project cost.

(viii) Power crisis in Uttar Pradesh and need for supply of additional power to the State.

15. hrs.

श्री बृबेन्द्र पाल सिंह (सम्भल): उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में आई भारी शिराबट के कारण किमानों को रबी की बुबाई व फसल की सिचाई के समय ट्यूब-वैल चलाने के लिए बिजली नहीं के बराबर मिल पा रही है। जितनी बिजली मिल रही है वह भी लगातार प्राप्त नहीं होने में द्यूबवैल बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। खास कर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्भल में। क्योंकि निर्वारित समय में भी बिजली बीच-बीच में चले जाने से ट्यूबवैल का पानी सेत तक नहीं पहुंचता है, गूल में ही रह जाता है।

किसान इस स्थिति से बहुत परेशान ऐ है। यह पलेबा व फसल की सिचाई करने का समय है। उत्तर प्रदेश सरकार का कथन है कि औबरा ताप विद्युत गृह के जल जाने के कारण विद्युत उत्पादन में जो कमी आई है, केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है।

कत: उर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिद्युत प्रदान करें ताकि किसान की रबी की बुवाई व पसल की सिचाई के वक्त ट्यूबवेल के लिए आवश्यक विद्युत प्राप्त हो सके।

(ix) Need for redressing the grievances of Loco Running Staff.

SHRI BASUDEB ACHARYA (Bankura): All India Loco Running Staff Association is organising a demonstration today at the Boat Club with the intention to represent their grievances before the Railway Minister. The Railway Administration has taken all measures in order to see that the workers cannot participate in the demonstration. Their own leave and passes were denied and they were being threatened with dire consequences.

The Loco Running Staff of Indian Railways are striving since long for redressal of their demands but they are being repressed and victimised and their problems remain unresolved. Their existing facilities have been curtailed and promotional policy has been changed. They are being forced to work for more than ten hours and are to work with sick rolling stock and engines. The active workers of their Association are under severe attack and are penalised and transferred for any trade union activity.

The convention of ILO decided to bring duty hours of workers to 8 hours. Purther, Inland Transport Committee under ILO decided that the duty hours of the workers should be brought to 40 hours a week. In both cases, the Government of India was a party to the